



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—काला ३—उप-वर्ग (१)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ५०]

१९८८ वर्ष, शनिवार, जनवरी ३०, १९८८/माघ १०, १९०९

No. ५०] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 30, 1988/MAGHA 10, 1909

इस नाम से भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

गृह संत्राय

नई दिल्ली, ३० जनवरी, १९८८

अधिसूचना

मा.का.नि. ६६(इ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्ननिवित उद्घोषणा संवैधानिक के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है—

यन् मध्ये, भारत के राष्ट्रपति श्री वेंकटरामन को समिलनाद्वय राज्य के शास्त्रपति में एक रिपोर्ट पास हुई है आर मुझे प्राप्त इस रिपोर्ट और अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मैंना समाधान ही गया है कि ऐसी स्थिति उत्तम हो गई है कि जिसमें कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान जिसे इसमें इससे पश्चात् “संविधान” कहा गया है के उपर्यांतों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है;

अन् अब मैं, गविधान के अनुच्छेद ३५६ द्वारा प्रदत्त अस्तियों का, तथा उस निमित्त सभी समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों द्वा प्रयोग करने द्वारा प्रतिरक्षण करता हूँ कि मैं—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के शास्त्रपति में निवित या एतद्वारा प्रयोग-सम्बन्ध सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने हाथ में लेता है;

(ख) घोषित करता हूँ कि उक्त राज्य वे विधान मंडल की शक्तिया समझ के प्राधिकार द्वारा या अधीन प्रयोगक्षम होगी; और

(ग) निम्ननिवित आनुषंगिक और परिणामिक उपबन्ध करता हूँ जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए मुझे आवश्यक या बोधनीय प्रतीत होती है, प्रथम—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्यक्त खण्ड (क) के आधार पर अपने हाथ में लिए गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में अभी भी तब जिस तक मैं ठीक समझूँ उक्त राज्य के शास्त्रपति के माध्यम से तारों परना विधिवृत्त झोगा,

(ii) उस राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्वारा निर्लिपित किया जाता है, प्रयत्नित—

अनुच्छेद 3 के परम्परुक का उतना भाग जिसने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निर्देश करने से है;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जिसने का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के राज्य विधान मंडल के समझ रखे जाने में है,

अनुच्छेद 163 और 164;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जिसने का संबंध राज्य सरकार के कार्यों का मन्त्रियों के बीच आवंटन से है; अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उतना भाग जिसने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प के पारित किया जाने गे हैं,

अनुच्छेद 174 का खंड (1), और खंड (2) का उपखंड (क); अनुच्छेद 175 से 178 तक जिसमें वे दोनों सम्मिलित हैं; अनुच्छेद 179 का खंड (ख) और (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परम्परुक और अनुच्छेद 180 और 181;

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जिसने का संबंध विधान सभा के उपायक्ष के संबंधमों और भूतों से है; अनुच्छेद 188, 189, 193, 194, 195 तथा 196; अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 199 का खंड (3) और खंड (4);

अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उतना भाग जिसने का संबंध विधान सभा के उपायक्ष के संबंधमों और भूतों से है; अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें यह दोनों सम्मिलित है) अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परम्परुक और खंड (3) का परम्परुक, दोनों

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जिसने का संबंध ज्ञापन संसदि रिपोर्ट को गवर्नर के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने में है;

(iii). उक्त गवर्नर की विधान सभा एवं द्वारा भग वी जानी है;

(iv) संविधान भग वाले विधान सभा एवं द्वारा भग वी जानी है;

अनुच्छेद 356 के विधान सभा के गवर्नर के प्रति निर्देश का अर्थ उस राज्य के संबंध में गवर्नर के प्रति निर्देश लगाया जाएगा और उसमें रोज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति जिसी निर्देश का, जहां तक उसका संबंध उसके कुल्यों और उसकी सक्षियों में है, अर्थ, जब तक कि संदर्भ में अत्यधिक अपेक्षित न हो, गंसद के प्रति निर्देश लगाया जाएगा. और विधिष्टतया अनुच्छेद 313 में राज्यपाल और गवर्नर के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति निर्देश का अर्थ क्रमः राष्ट्रपति और प्रधान या उसके सदनों के प्रति निर्देश लगाया जाएगा

परन्तु इसमें कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से अकर अनुच्छेद 159 तक जिसमें वे दोनों भाग सम्मिलित हैं, अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 301 तथा 151 की विधिका के पैरा 1 से 4 तक जिसमें वे दोनों भाग सम्मिलित हैं के उपबंधों पर प्रभाव नहीं आती और न राष्ट्रपति को उम्में खंड के उपखंड (i) के अधीन उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी;

(v) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या एतद्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानों उसके अंतर्गत इस उद्धोषण के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) और तमिलनाडु संघ अधिनियम 1891 (1891 का तमिलनाडु अधिनियम 1) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करने हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निर्देश है, और साधारण खंड अधिनियम 1897 (1897 के दर्पणों) का उतना भाग जिसना राज्य विधियों पर आया है, ऐसे जिसी अधिनियम या विधि के द्वारा में ऐसे प्रभावी होगा मानो यह उन राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियम हो।

नई दिल्ली,
दिनांक 30 जनवरी 1988

(आर. वेकटरामन)
नामपति

नई दिल्ली, [का.स V/11013/1/88-सो एम.भार.]
दिनांक 30 जनवरी, 1988 मी.० जी० सामैया, ननिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th January, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 66(E).—The following Proclamation by the President is published for general information :

Whereas, I, R. Venkataraman, President of India, have received a report from the Governor of the State of Tamil Nadu and after considering the report and other information received by me I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution, and of all other powers enabling me in that belief, I hereby proclaim that I—

- assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;

(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely :—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely :—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167 and so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1), and sub-clause (a) of clause (2), of article 174; articles 175 to 178 (both inclusive); clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 188, 189, 193, 194, 195 and 196; article 198; clauses (3) and (4) of article 199;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 208 to 211 (both inclusive), the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved;

(iv) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference thereto in the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively :

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(v) any reference in the Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Tamil Nadu General Clauses Act, 1891 (Tamil Nadu Act 1 of 1891), as in force in the State of Tamil Nadu, and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

New Delhi.

The 30th January, 1988.

(R. VENKATARAMAN
PRSFIDPN)

New Delhi.

The 30th January, 1988.

(No. F. V 11013188-CSRI
C. G. SOMIAH, Home Secy.

प्रादेश

नं दिल्ली, 30 जनवरी, 1988

मा.का.नि. 67(ग) —राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित श्रद्धेश भवेमाधारणे के मन्त्रनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रयोग परे द्वारा आज 30 जनवरी 1988 दिन जारी हो गये उल्लंघणा

के खड़ (ग) के उपग्रह (1) का अनुसरण करते हुए, मैं एतद्वारा निर्देश द्वारा हूँ कि तमिलनाडु राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के प्रधीन या उस गज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस गज्य के गत्यपात्र में निहित या प्रयोगत्व मर्मांशकिया, जिनको राष्ट्रपति न उक्त उद्घोषणा के खड़ (क) के श्राधार पर ग्राहने हाथ में ले लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निर्देश और नियन्त्रण के अध्याधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

नई दिल्ली, (आर. वेंकटरामन)
दिनांक 30 जनवरी, 1988 राष्ट्रपति

नई दिल्ली, [फा सं. V/11013/1/88-सी. एस. आर.]
दिनांक 30 जनवरी 1988 सी. एस. आर. सोमिया, सचिव

ORDER

New Delhi, the 30th January, 1988

G.S.R. 67(E).—The following Order by the President is published for general information :—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 30th day of January, 1988 by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Tamil Nadu and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi,
The 30th January, 1988

(R. VENKATARAMAN)
PRESIDENT

New Delhi,
The 30th January, 1988.

[F. No. V/11013/1/88-CSR]
C. G. SOMIAH, Home Secy.